

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—277 / 2015 / 223 (2015 / 00151)

1. हीरा पुत्र स्व० चांदा पौत्र स्व० कज्जा, जाति चीता, नि० सोमलपुर, तह० व जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम शहबुद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर, जाति चीता नि० सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर ।
2. रूपा पुत्र स्व० चांदा पौत्र स्व० कज्जा, जाति चीता, नि० सोमलपुर, तह० व जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसान:—
  - 2/1— श्रीमती सायरी पत्नि रूपा जाति चीता,
  - 2/2— नसीर पुत्र रूपा, जाति चीता,
  - 2/3— सईदा पुत्री रूपा, जाति चीता,
  - 2/4— रशीदा पुत्री रूपा, जाति चीता,
  - 2/5— रमजानी पुत्री रूपा, जाति चीता,2/1 से 2/5 जरिये मुख्तयारआम शहाबुद्दीन पुत्र मोहम्मद नूर, जाति चीता, नि० सोमलपुर, तह० व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. श्रीमती कमला पुत्र स्व० चांदा, जाति चीता, नि० सोमलपुर, तह. व जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 3.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 97 / 2010.

उपस्थित:—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो० संख्या 1 .
3. श्री ताराचंद कुर्दिया, वकील रेस्पो० संख्या 3.

निर्णय

दिनांक:—10.04.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने अधी०न्याया० में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोमलपुर, तहसील व जिला अजमेर में स्थित भूमि जिसके चौसाला खसरा नंबर 2583 मिन जिसके वर्किंग खसरा नंबर 3037 रकबा 6-6-0 की भूमि के खातेदार चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता संख्या 497 के चौसाला खसरा नंबर 2583 मिन रकबा 7 बीघा एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 221 के अनुसार खातेदार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता दर्ज है, अपीलाधीन भूमि जिसके चौसाला जमाबंदी के अनुसार खातेदार चांदा पुत्र कज्जा थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान अपीलांटस है किन्तु भू-प्रबंध विभाग ने विवादित आराजी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के सिवायचक दर्ज

कर दिया । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी०न्याया० ने [वादीगण/अपीलांटस](#) का वाद खारिज कर दिया । अधी०न्याया० के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया । रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसके चौसाला खसरा नंबर 2584 मिन रकबा 7 बीघा के खातेदार चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता नंबर 497 के अनुसार एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 221 के अनुसार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता थे परन्तु वर्किंग जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी पूर्ववत् चौसाला जमाबंदी के प्रतिकूल इंद्राज भू-प्रबंध विभाग, अजमेर के द्वारा किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण इंद्राज है । भू-प्रबंध विभाग को पूर्व इंद्राज को परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित कर दिया । अधी०न्याया० ने वाद को निर्णित करने से पूर्व में वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात भी कायम नहीं की है । अधी०न्याया० के समक्ष वादी संख्या 2/3 सलीम का स्वर्गवास हो चुका था जिसका नाम वादपत्र में से तर्क किये जाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधी०न्याया० ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । विवादित भूमि [अपीलांटस/वादीगण](#) की पुश्तैनी बापोती की ख्वातेदारी भूमि है एवं पुश्तैनी समय से चांदा एवं इनके स्वर्गवास के बाद अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अपीलांटस ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में अधी०न्याया० के समक्ष खसरा गिरदावरियां, चौसाला जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, वर्किंग जमाबंदी पेश की थी किन्तु अधी०न्याया० ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के संबंध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है । भू-संशोधन की जमाबंदी संवत् 2027 के अनुसार भी खातेदारी इंद्राज दर्ज है, भू-संशोधन जमाबंदी के इंद्राज के अनुकूल ही राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचना एवं नियम 20-क के अनुसार भी अपीलाधीन भूमि जो कि वादीगण की बापोती भूमि है का इंद्राज वर्तमान जमाबंदी में वादीगण के नाम किया जाना चाहिये था किन्तु अधी०न्याया० ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा [वादीगण/अपीलांटस](#) का वाद निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा [वादीगण/अपीलांटस](#) को वाद में चाहे गये अनुतोष के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।
5. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । विवादित चौसाला जमाबंदी में सिवायचक दर्ज होने से वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज की गई है यह इंद्राज विधिसम्मत है । अपीलांटस विवादित भूमि पर मात्र अतिक्रमी है जिसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

विवादित भूमि चौसाला खसरा नंबर 2583 मिन जिसके वर्किंग खसरा नंबर 3037 रकबा 6-6-00 के खातेदार पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के खाता संख्या 497 में एवं जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के खाता संख्या 221 के अनुसार चांदा पुत्र कज्जा जाति चीता दर्ज है एवं वर्किंग खसरा नंबर 3037 रकबा 6-6-00 के खातेदार हीरा व रूपा पि० चांदा वर्किंग जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 में दर्ज है । उक्त भूमि नामांतरण संख्या 533 दिनांक 6.4.1967 के अनुसार धारा 15 राज०काश्त०अधि० के तहत चांदा वल्द कज्जा के नाम हक खातेदारी देकर नामांतरण स्वीकृत किया गया था तदनुसार राजस्व अभिलेख में चांदा वल्द कज्जा को खातेदार दर्ज किया जाना जाहिर होता है । खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2026 तक विवादित भूमि पर काश्त किया जाना प्रमाणित होता है परन्तु वर्किंग जमाबंदी में चौसाला खसरा नंबर 2583 के वर्किंग खसरा नंबर 3037 को भू-प्रबंध विभाग द्वारा सरकारी दर्ज कर दी गई इस कारण अधी०न्याया० के समक्ष [वादीगण/अपीलांटस](#) द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया परन्तु अधी०न्याया० द्वारा उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा कर बिना साक्ष्य लिये एवं बिना तनकियात कायम किये वाद को कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दौराने वाद वादी संख्या 2/3 सलीम एवं वादिया संख्या 3 हगामी का भी स्वर्गवास हो गया था जिनके नाम तर्क किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये थे परन्तु अधी०न्याया० उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई निर्णय दिये बिना मृतक के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी०न्याया० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर